



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 26 अक्टूबर, 2020 ई0

कार्तिक 04, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 387/XXXVI (3)/2020/59(1)2020

देहरादून, 26 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड (जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956) (संशोधन) विधेयक, 2020’ पर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्या: 31 वर्ष, 2020 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

**उत्तराखण्ड (जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956)
(संशोधन) अधिनियम, 2020**

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 31, वर्ष 2020)

जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, वर्ष 1956) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956) (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) इसका विस्तार जिला देहरादून के समस्त जौनसार-बावर परगना में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 32 का
संशोधन

2. जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, वर्ष 1956) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 32 में एक नया खण्ड '(घ)' निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-

"(घ) जिला देहरादून के समस्त जौनसार-बावर परगनें के ऐसे सभी व्यक्ति जो वर्ग 4 की भूमि पर दिनांक 30.06.1983 तक अथवा उससे पूर्व, अनाधिकृत रूप से काबिज थे तथा सम्प्रति इस भूमि पर काबिज हैं, को सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप"

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव।

कारण और उद्देश्य

जिला देहरादून के जौनसार-बावर परगनें में वर्ग-4 की भूमि पर अनाधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों को भूमि विनियमित किया जाना समीचीन है, जिसकी पूर्ति हेतु जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 की धारा-32 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

2- प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री।

No. 387/XXXVI(3)/2020/59(1)/2020
Dated Dehradun, October 26, 2020

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand (The Jaunsar-Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956) (Amendment) Act, 2020' (Act No. 31 of 2020).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 22 October, 2020.

**THE UTTARAKHAND (THE JAUNSAAR-BAWAR ZAMINDARI ABOLITION
 AND LAND REFORMS ACT, 1956) (AMENDMENT) ACT, 2020**

(Uttarakhand Act No. 31 of 2020)

AN

ACT

further to amend (The Jaunsar-Bhawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956) (U.P. Act no 11 of 1956) (as applicable in state of Uttarakhand) in the context of the State of Uttarakhand;

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy-first year of the Republic of India as follows:-

- | | | |
|---|----|---|
| Short title,
extent and
Commencement | 1. | (1) This Act may be called the Uttarakhand (The Jaunsar-Bhawar Zamindari Abolition And Land Reforms Act, 1956 (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall extends to the whole Jounsar-Bhawar sub division of district dehradun.

(3) It shall come into force at once. |
| Amendment of
Section 32 | 2. | In Section 32 of The Jaunsar-Bhawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956 (U.P. Act no 11 of 1956) (as applicable in state of Uttarakhand) a new clause (D) shall be inserted as follows, namely:-

"D. All such person of the whole Jaunsar-Bhawar sub division of District Dehradun who were in unauthorised possession of the category-4 land on or before the date of 30.06.1983 and presently having possession on this land, as per the procedure prescribed by the government". |

By Order,

PREM SINGH KHIMAL,
 Secretary.

Statement of objectivs and Reasons

It is necessary to give benefits of regulizaton to all persons having possession in unauthorised form of the category-4 land in Jaunsar-Bhawar sub division of District Dehradun for fulfillment of which amendment in section 32 of Jaunsar-Bhawar Zamindari Abolition Land Reforms Act, 1956 is proposed.

2- The proposed Bill full fill in the aforesaid objectives.

Trivendra Singh Rawat
Chief Minister.

धान
यम,
और
के